515

दृष्टि The Vision

drishti

GENERAL STUDIES (Test–18)

निर्धारित समय: तीन घंटे Time allowed: Three Hours	GSM (M-I)-2418	अधिकतम अंक: 250 Maximum Marks: 250

Name: DEEPAK MEENA **Mobile Number:**

Medium (English/Hindi): HINDI **Reg. Number:**

Center & Date: M.N. 21/08/2024 **UPSC Roll No.** *(If allotted)*: 5812616

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

*इसमें **बीस** प्रश्न हैं तथा **हिन्दी** और **अंग्रेज़ी** दोनों में छपे हैं।*

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and **ENGLISH.***

All the questions are compulsory.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा भरा जाए *(To be filled by Evaluator only)*

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.		11.	
2.		12.	
3.		13.	
4.		14.	
5.		15.	
6.		16.	
7.		17.	
8.		18.	
9.		19.	
10.		20.	
Grand Total (सकल योग)			

मूल्यांकनकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Reviewer (Signature)

Feedback

1. Context Proficiency (संदर्भ दक्षता)
2. Introduction Proficiency (परिचय दक्षता)
3. Content Proficiency (विषय-वस्तु दक्षता)
4. Language/Flow (भाषा/प्रवाह)
5. Conclusion Proficiency (निष्कर्ष दक्षता)
6. Presentation Proficiency (प्रस्तुति दक्षता)

drishti | दृष्टि The Vision

1. संसदीय उत्तरदायित्व के स्तर को निर्धारित करने में विपक्षी दलों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। चर्चा कीजिये।
(150 शब्द) 10

The role of opposition parties is critical in determining the level of parliamentary accountability. Discuss.
(150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

संसदीय व्यवस्था में विपक्षी दल कार्यपालिका से प्रश्न करके उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते है।

भूमिका

- अनुदान की माँगो पर विचार-विमार्श, प्रश्न, कटौती प्रस्ताव आदि लाना
- अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा लोक महत्व के मुद्दो पर चर्चा करना
- संख्या संतुलन की स्थिति में विभिन्न विधेयको पर विपक्ष के साथ सहमति बनाकर विधेयक पास करने से वृहद् जनप्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है।
- लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति,

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

आदि के माध्यम से कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण एवं जवाबदेहिता।

सीमाएँ

- राजनीतिक साँठ गाँठ आधारित विरोध करना
- पार्टियों में ~~सम~~ विचारात्मक प्रतिबद्धता का अभाव
- धनबल की राजनीति
- सभी सदस्यों को समय न मिलना
- सदस्यों की उपस्थिति में कमी

आगे की राह

- न्यूनतम सदस्य उपस्थिति का प्रावधान
- प्रत्येक बिल पर चर्चा की अनिवार्यता
- सांसदों का प्रशिक्षण

विपक्ष की भूमिका को जे.एस. मिल के उपयोगितावाद से समझा जा सकता है जिनके अनुसार "एक विरोधी मत भी उपयोगितावाद है"

drishti | दृष्टि The Vision

2. महिलाओं की श्रम बल भागीदारी को बढ़ाने में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10
Discuss the role of Self-Help Groups in widening women's labour force participation. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारत में लगभग 88 लाख स्वयं सहायता समूह हैं जिनमें से 90% से अधिक महिलाओं द्वारा संचालित है।

महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी
- PLFS के अनुसार 37% (वैश्विक औसत - 47%)

कारण
- महिलाओं पर सामाजिक उत्तरदायित्व
- शिक्षित महिलाओं में कार्य के प्रति उदासीनता
- पुरुषसत्तात्मक मानसिकता
- कार्य स्थल पर असुरक्षा
- वेतन अंतराल
  - WEF की GGP में भारत का 135वाँ स्थान)

SHG की भूमिका
- पारिवारिक कार्य के साथ करना संभव

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

↳ रोजगार की स्थानीय उपलब्धता
↳ SHGs में सामूहिक स्वामित्व का बोध (सहकारिता - अमूल)
↳ अनौपचारिक क्षेत्र (90%) को औपचारिक क्षेत्र में लाने की संभावना
↳ जागरूकता व सहभागिता में वृद्धि

आगे की राह

↳ SHGs को प्रोत्साहन तकनीकी क्षेत्र में (लखपति दीदी योजना)
↳ SHGs द्वारा नवोन्मेष (तिलोनिया कॉलेज राजस्थान)

DPSP में 97 वें संविधान संशोधन द्वारा Art. 43B का समायोजन, सहकारिता मंत्रालय का पृथक स्वतंत्र निर्माण आदि SHGs की विकास की भूमिका के समान है।

3. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलने से समाज के कल्याण के प्रति समग्र दृष्टिकोण को बल मिला है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

The approach to welfare is wholesome and whole-of-society, with increasing private sector participation through Corporate Social Responsibility(CSR). Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के आधार CSR को अनिवार्यता प्रदान करने वाला भारत विश्व का प्रथम देश है।

CSR → कोरपोरेट क्षेत्र का समाज के प्रति दायित्व

- 5 करोड लाभ
- 500 करोड टर्नओवर
- 1000 करोड सम्पत्ति

} 2% अर्जित लाभ का

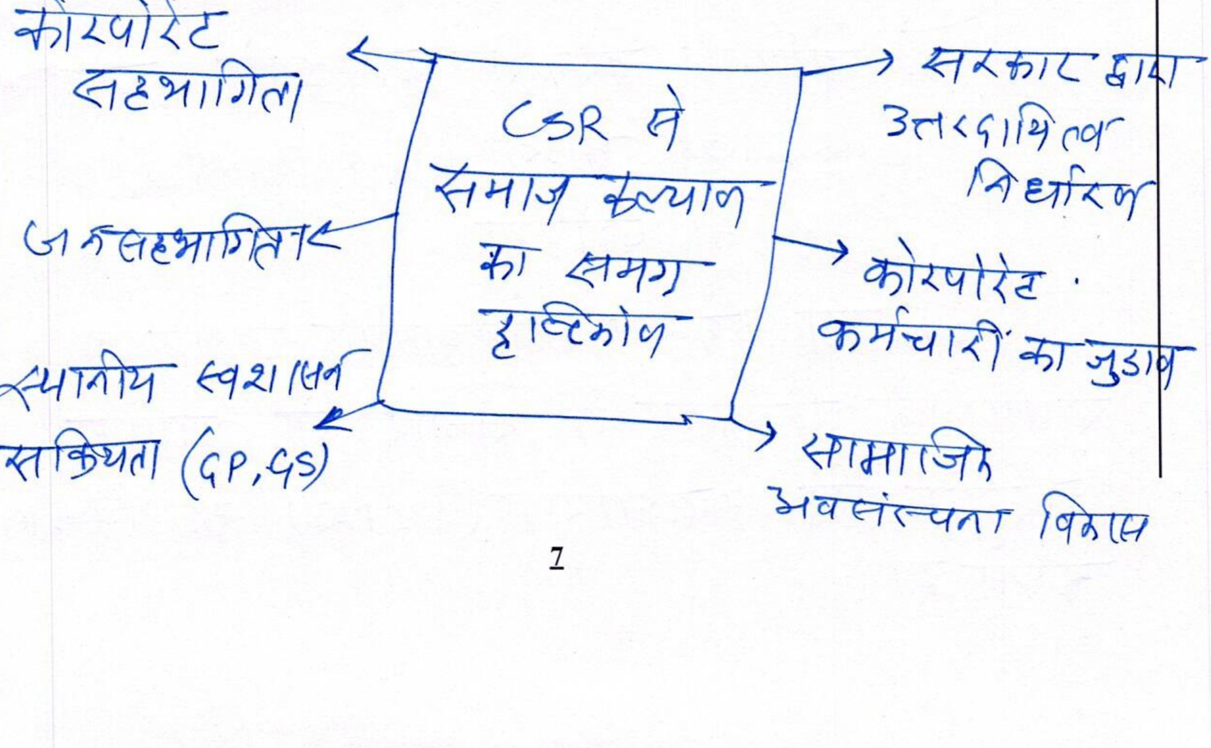

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

सीमाएँ

- वैधानिक अनिवार्यता के दबाव में औपचारिकता पूर्ण CSR गतिविधियाँ करना
- व्यवस्थित नियंत्रण व्यवस्था का अभाव
- प्रभाव आकलन (Outcome/Performance) की कमी

आगे की राह

- इंजेती श्रीनिवास समिति की सिफारिशें लागू करना
- MCA के अंतर्गत CSR Trust द्वारा CSR फंड संग्रहण व निष्पादन करना
- विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों यथा एकलव्य मॉडल स्कूल आदि से CSR को जोड़ना

CSR का उद्देश्य व्यवसायिक जगत में सामाजिक संवेदना के संचार से व्यापक सहयोग की अवधारणा (WIPRO) का विकास करना है।

drishti | दृष्टि The Vision

4. व्यक्तिगत और राष्ट्रीय विकास के क्रम में मानसिक स्वास्थ्य, कम ध्यान दिये जाने वाला लेकिन प्रभावशाली चालक है। चर्चा कीजिये। इस संबंध में सरकार की सकारात्मक नीति क्या है? (150 शब्द) 10

Mental health is a less seen yet principally impactful driver of individual and national development. Discuss. What is the Government's positive policy momentum in this regard? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

मस्तिष्क, मनुष्य शरीर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। अतः इसका स्वस्थ रहना मानव स्वास्थ्य का अपरिहार्य घटक है।

मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता

- बेहतर शिक्षा
- कौशल
- उत्पादकता पूर्ण कार्य निष्पादन
- स्वास्थ्य खर्च कम ⇒ पूर्ण स्वास्थ्य
- बेहतर श्रम बल ⇒ उत्पादन ↑ ⇒ संवृद्धि
- आत्महत्या जैसे नकारात्मक विचारों से दूरी

सरकार की सकारात्मक नीति

- राष्ट्रीय मानसिक रोग निवारण नीति
- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

से योग का प्रसार कर तनाव, चिंता आदि से बचाव करना

लोक सेवकों के लिए

- LTC
- PM कर्मयोगी के माध्यम से तनाव प्रबंधन
- कार्य घंटो का निर्धारण
- CGHS

सीमाएँ

- मानसिक रोग को पागलपन समझना
- जागरूकता का अभाव
- रोगियों को स्वयं ज्ञात न होना
- बताने में हिचकना

आगे की राह

- नई शिक्षा नीति में स्वास्थ्य शिक्षा के साथ मानसिक स्वास्थ्य शामिल करना
- जागरूकता अभियान (AIDS कीतरह)

"Positivity tends to Positive Results"

drishti | दृष्टि The Vision

5. ग्रामीण भारत के शासन में सुधार हेतु शुरू की गई विभिन्न डिजिटलीकरण पहलों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

Discuss the multiple digitization initiatives that have been unfolding in rural India to improve governance. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

डिजिटल भारत योजना के अंतर्गत भारत में इंटरनेट उपयोग ~~कर्ता~~ शहरी क्षेत्रों में 67% लोगो द्वारा तथा ग्रामीण क्षेत्रो 34% लोगो ~~4~~-तक पहुँचा है।

डिजिटलीकरण पहलें

- भारत नेट परियोजना → 6 लाख ग्राम ~~पंचायतो~~ तक ब्रांडबैंड सेवाएँ
- USOF की स्थापना
- डिजिटल भारत के अंतर्गत → जनता, अवसंरचना, साधन — विकास
- भू अभिलेखो का डिजिटलीकरण DILRM 2008
- e- शासन
- e-NAM - मंडियों का जुड़ाव

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

↳ राज्य स्तरीय G2C सेवाएँ
(राजस्थान - SSO, MP- सरकारonline)
↳ ESC द्वारा सेवाएँ
↳ UMANG, DigiLocker.

सीमाएँ
↳ भारत नेट परियोजना का धीमा क्रियान्वयन
(केवल 60% कार्य पूर्ण)
↳ शहरी-ग्रामीण विभाजन
↳ डिजिटल साक्षरता
↳ साइबर शिक्षा व सुरक्षा

आगे की राह
↳ इंटरनेट का अधिकार
↳ e-शासन क्रांति
↳ श्रीनिवास समिति अनुशंसित डेटा सुरक्षा कानून

भारत को डिजिटल भारत से आगे बढ़कर सुरक्षित एवं डिजिटल साक्षर भारत की ओर कदम बढ़ाने की आवश्यकता है।

drishti | दृष्टि The Vision

6. भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस लिखित संघीय संविधान को नम्यता (Flexibility) प्रदान करने का प्रयास किया गया है। विस्तारपूर्वक समझाइये। (150 शब्द) 10

A distinctive feature of the Indian Constitution is that it seeks to impart flexibility to a written federal Constitution. Elaborate. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान में कठोरता एवं नम्यता का मिश्रण है और संविधान लागू होने (26 जनवरी 1950) से अब तक 106 बार संविधान संशोधन किए जा चुके है।

लिखित संघीय संविधान - नम्यता

→ USA का लिखित संघीय संविधान कठोर संविधान है जिसमें संविधान-संशोधन की जटिल प्रक्रिया है- और सभी राज्यों की सहमति आवश्यक है।

भारत → कठोरता / नम्यता

कठोरता	नम्यता
संघीय विषयों पर दोनों सदनों का विशिष्ट बहुमत	संसद के दोनों सदनों के

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

तथा आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित होना (राष्ट्रपति-चुनाव) GST	विशिष्ट बहुमत से संशोधन (अनु० - EWS आरक्षण)

औचित्य

- → विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ
- → परिसंघात्मक व्यवस्था (कनाडा संघीय व्यवस्था)
- → विविधता का समावेशन के साथ राष्ट्रीय एकता की सुनिश्चितता
- → मूल ढाँचे की अपरिवर्तनीयता का सिद्धांत (केशवानंद भारती वाद
- → संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धान्त

भारतीय संविधान जीवन्त एवं प्रगतिशील दस्तावेज है जिसमें समय के परिवर्तन के साथ तार्किक परिवर्तन करना इसकी प्रासंगिकता की आवश्यकता है।

drishti | दृष्टि The Vision

7. न्यायिक कार्यों की पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता एक सुदृढ़ एवं प्रभावी विधिक प्रणाली की आधारशिला है, जिससे लोक विश्वास सुनिश्चित और न्यायिक सिद्धांत का कार्यान्वयन संपुष्ट होता है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

The transparency and accountability of judicial function form the cornerstone of a robust and effective legal system, ensuring public trust and upholding the principles of justice. Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

लोकतंत्र में न्यायपालिका के माध्यम से विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्यों पर नियंत्रण एवं संतुलन स्थापित कर डायसी का विधि का शासन सुनिश्चित किया जाता है।

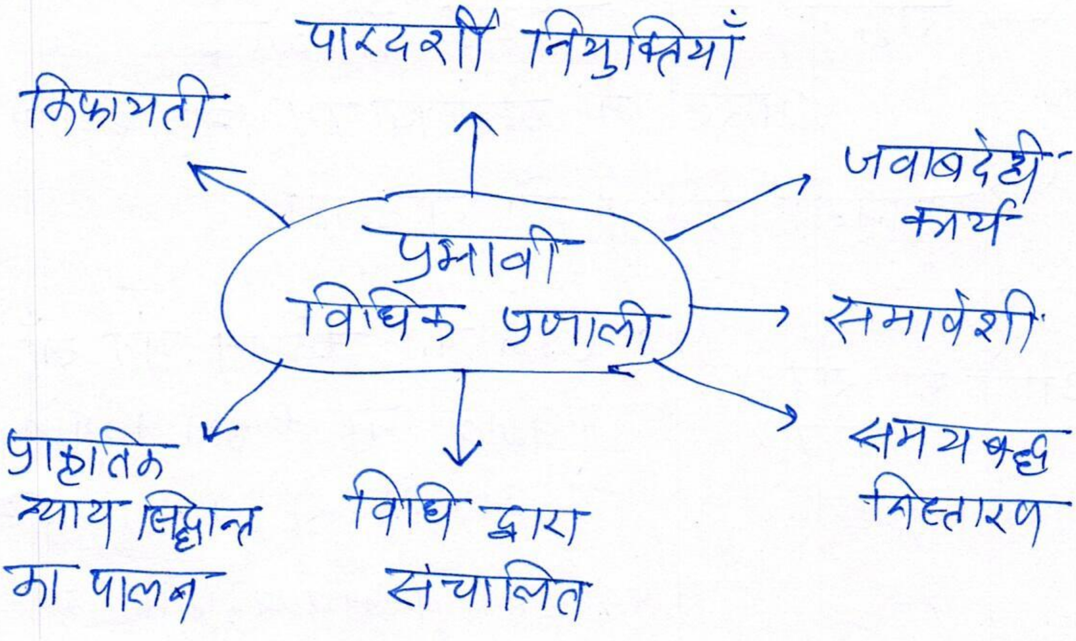

प्रभावी विधिक प्रणाली के परिणाम

→ दोषियों को सजा से आमजन में

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

सुरक्षा एवं विश्वास की भावना

↳ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन तथा अस्पष्ट/अप्रासंगिक विधि होने पर यथोचित प्रक्रिया के सिद्धान्त के अनुसार न्याय प्रदान करना

सीमाएँ

↳ सिद्धान्त एवं व्यवहार में अंतर (भारत में कॉलेजियम नियुक्तियाँ)

↳ कानूनी प्रक्रिया की जटिलता

आगे की राह

→ USA का कॉमन मैन लॉ सिद्धान्त पर कानून निर्माण जो आसानी से समझा जा सके

→ पारदर्शिता व जवाबदेहिता के साथ समयबद्धता, वहनीयता के प्रावधान करना

भारत में प्रभावी NALSA क्रियान्वयन से सभी के लिए न्याय की प्राप्ति की जा सकती है

drishti | दृष्टि The Vision

8. राज्यों की राजनीतिक कार्यप्रणाली के संबंध में राज्यपालों के गैर-पक्षपातपूर्ण बने रहने से संबंधित संवैधानिक अवधारणा गहन जाँच के दायरे में है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

The constitutional conception of state governors occupying a non-partisan position with regard to the political functioning of states has come under severe strain. Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान में राज्य कार्यपालिका के प्रमुख के रूप राज्यपाल के पद का प्रावधान है जो केन्द्र व राज्य के मध्य सेतु का कार्य करता है।

चिंता

- केन्द्र सरकार द्वारा राजनीतिक टकराव की हित पूर्ति के लिए राज्यपाल पद का दुरुपयोग करना
- राज्यपाल के द्वारा निर्वाचित सरकार/मंत्रिपरिषद् की सलाह अनुसार कार्य न करना (केरल, तमिलनाडु)

अनुशंसाएँ

- पूँछी आयोग तथा सरकारिया आयोग राज्य के बाहर के व्यक्ति को राज्यपाल

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

नियुक्ति की अनुशंसा की थी

↳ राज्यपाल नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री की सलाह

↳ राज्यपाल का निश्चित कार्यकाल

↳ बोम्मई राज वाद 1994 में SC ने राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना बाध्यकारी माना (अपवाद- विवेकाधीन शक्तियाँ)

आगे की राह
→ विधेयकों पर निर्णय की समय सीमा निर्धारित
→ विवेकाधीन शक्तियों का स्पष्ट वर्णन
→ राजनीतिक टकराव का जन कल्याण के मुद्दों पर बीच में न लाना

राज्यपाल संवैधानिक पद है अतः पदधारण करने वाले व्यक्ति को सर्नैतिकता का पालन करके पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए

डा० APJ अब्दुल कलाम – राष्ट्रपति

9. "कारागार सुधार न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है, बल्कि एक विधिक एवं सामाजिक आवश्यकता भी है।" इस कथन के आलोक में भारत में कारागारों की स्थिति का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द) 10

"Prison reform is not just a moral imperative, but a legal and social necessity." In light of this statement, critically analyze the state of prisons in India. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत के कारागारों में बंद कैदियों में अधिकांश विचाराधीन कैदी है जो अपने आरोपित अपराध की सजा का अधिकतम भाग जेल में काट चुके है।

कारण

- धीमी न्यायिक प्रणाली
  - सिविल मामला औसत - 2.5 वर्ष
  - आपराधिक मामला औसत - 3 वर्ष
- अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पद
- जेल राज्य सूची का विषय अतः राज्यवार भिन्नता
- कारागार अधिनियम 1894 में ब्रिटिश शोषणकारी मानसिकता
- जेलों की खराब अवसंरचना/क्षमता/स्थिति

drishti दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

नैतिक अनिवार्यता
→ अपराध से घृणा करो अपराधी से नही - गाँधीजी

विधिक
→ अनुच्छेद 21 में गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार कैदियों के लिए भी है
→ विचाराधीन कैदियों का सजा काटना स्वतंत्रता के अधिकार का हनन

सामाजिक
→ न्याय व्यवस्था के प्रति अविश्वास
→ अपराधिकरण को अवधारणात्मक आधार

आगे की राह
→ मालिमथ समीति के अनुसार जेल सुधार
→ न्यायिक अभिरक्षा कैदियों को सुविधाओं का अधिकार
→ मॉडल जेल अधिनियम

जेल अपराधियों के सजा के साथ सुधार के लिए होते है अतः सकारात्मक वातावरण होना आवश्यक है

drishti | दृष्टि The Vision

10. भारत में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए इसके कार्यान्वयन संबंधी प्रमुख मुद्दों एवं चुनौतियों पर प्रकाश डालिये। (150 शब्द) 10

Discuss the need for an All-India Judicial Service (AIJS) in India, highlighting key issues and challenges in its implementation. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में AIJS की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

मुद्दे →

- भिन्न राज्यों के भिन्न कानून
- भाषायी विविधता
- संघीय अवसंरचना के आधार पर विरोध
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता
- AIJS पर अंतिम नियंत्रण

चुनौतियाँ

- राज्यों की सहमति प्राप्त करना
- संवैधानिकता (NJAC को SC ने असंवैधानिक घोषित किया था)
- विधायी प्रावधान के लिए संसदीय

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

सहमति प्राप्त करना

~~आग~~ संभावित लाभ AIJC/आवश्यकता

→ रिक्त पदों की समयबद्ध भर्ती

→ लम्बित मामलों में कमी

→ न्यायिक प्रणाली में विश्वसनीयता

→ अखिल भारतीय प्रतिभा के शामिल होने से कुशल न्यायाधीशों के लिए स्वच्छ प्रतिस्पर्धा

→ उच्च न्यायपालिका में अनुभवी व युवा सहभागिता

आगे की राह

→ राजनीतिक सहमति बनाना

→ संविधान के मूल ढाँचे के अंतर्गत विधायी प्रावधान

न्यायपालिका को विधायिका व कार्यपालिका के साथ सहयोगात्मक संबंध बनाकर न्याय प्रणाली में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए

drishti | दृष्टि The Vision

11. सराहनीय प्रयासों के बावजूद, भारत की जनजातीय जनसंख्या तक स्वास्थ्य सेवाओं के सफल वितरण में विभिन्न चुनौतियाँ विद्यमान हैं। विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

Despite commendable efforts, there are several obstacles that hinder the successful delivery of healthcare services to the tribal population of India. Analyse. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

2011 जनगणना के अनुसार भारत में 8.6% जनसंख्या जनजातीय समुदायों की है जिनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति सामान्यत: पिछड़ी हुई है।

प्रयास

- आयुष्मान भारत (PM-JAY) योजना के अंतर्गत 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा
  - SECC 2011 के 7 संकेतकों में अनुसूचित जनजाति संकेतक में लाभार्थी शामिल
- ई. संजीवनी द्वारा टेलीमेडिसिन
- डॉक्टरों की संख्या में वृद्धि (1 : 837)
  - AYUSH प्रणाली डॉक्टर शामिल
- AYUSH पद्धतियों का प्रसार

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

↳ स्वास्थ्य पर खर्च को GDP के 1.6% से बढ़ाकर 2.1% तक लाया गया

↳ आयुष्मान भारत योजना में वेलनेस सेंटर के रूप में प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं पर फोकस

चुनौतियाँ

↳ शहरी-ग्रामीण विभाजन की स्थिति
  - → 70% स्वास्थ्य संरचना शहरों में
  - → 75% जनजातियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में

↳ 75 PVTGs का दुर्गम क्षेत्रों में निवास

↳ जनजातियों में आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के प्रति उदासीनता

↳ अंधविश्वास की उपस्थिति

↳ सामाजिक अवसंरचना के प्रति जनजातियों में अपनत्व भाव की कमी

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

↳ आधुनिक चिकित्सा पद्धतियाँ महंगी
↳ 65% जनजातियाँ गरीबी रेखा के नीचे

आगे की राह

↳ राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के लक्ष्यों के अनुसार स्वास्थ्य पर GDP का 3% व्यय

↳ लोकुर समिति की अनुशंसा अनुसार जनजातियों को मुख्य धारा में लाना

↳ AYUSH पद्धतियों का विकास से जनजातियों में विश्वसनीयता बढ़ाना।

जनजातियों तक स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करके ही SDG-3 के सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है।

drishti | दृष्टि The Vision

12. विधायी अंग के रूप में संसदीय कार्यों की गणना कीजिये। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि संसदीय संस्था और उसकी प्रक्रियाओं को प्रभावी बनाने हेतु सुधार एवं तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई अनिवार्य है? (250 शब्द) 15

Enumerate the functions of Parliament as the legislative organ. Do you agree that reforms and urgent remedial action seem imperative for making parliamentary institutions and processes effective? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

संसदीय प्रणाली का मुख्य आधार उत्तरदायित्व एवं शक्ति का पृथक्करण है। इसमें संसद का मुख्य कार्य विधि निर्माण करना है।

संसदीय कार्य

- विधि का निर्माण करना
- सरकार से विभिन्न मुद्दों पर सवाल पूछकर जवाबदेहिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना
- कार्यपालिका के कार्य निष्पादन के लिए धन संबंधी विनियोग प्रस्तावों का तार्किकरण तथा मंजूरी
- प्रश्न काल, शून्य काल, अल्पकालिक

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

चर्चा आदि माध्यमों से जनता की बात को कार्यपालिका तक पहुँचना

↳ संसदीय समितियों द्वारा विधेयकों की समीक्षा एवं अनुशंसाएँ करना

↳ CAG, UPSC, NCST जैसे संवैधानिक निकायों की वार्षिक प्रतिवेदन का आकलन करना

सीमाएँ

↳ संसदीय कार्य दिवसों की संख्या में लगातार गिरावट (1950-110, 2023-63)

↳ दल बदल कानून के कारण संवाद के स्तर, गुणवत्ता में गिरावट

↳ बिना संवाद के विधेयकों का पास होना

↳ 17वीं लोकसभा विपक्ष के लगभग सभी सांसदों का निलम्बन

↳ विपक्ष द्वारा प्रभाविकता से मुद्दे न उठा पाना

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

↳ सांसदों के पास अनुसंधान टीम का अभाव

↳ राजनीति का अपराधीकरण

↳ धन के बदले प्रश्न जैसे अनैतिक मुद्दे

आगे की राह / सुधार

↳ न्यूनतम कार्य दिवसों का विधायी प्रावधान

↳ दल बदल कानून के अंतर्गत व्हिप का प्रयोग सीमित (अविश्वास प्रस्ताव आदि)

↳ चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाना (दिनेश गोस्वामी समिति)

↳ प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट बनाना (ध्वनि मत के स्थान पर प्रत्यक्ष मत आदि)

संसदीय शासन में दिन प्रतिदिन का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना आवश्यक है इसके लिए उत्तरदायी कार्यपालिका व मजबूत विपक्ष एक दूसरे के पूरक हो

drishti | दृष्टि The Vision

13. वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र कम विरोधाभासी होने के साथ विवादों को सुलझाने के पारंपरिक तरीकों का बेहतर विकल्प प्रदान कर सकते हैं। चर्चा कीजिये। इस दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गए हैं? (250 शब्द) 15

Alternate Dispute Resolution mechanisms are less adversarial and can provide a better substitute to the conventional methods of resolving disputes. Discuss. What are the government's efforts to bring out a transformative shift towards it? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय न्यायपालिका में 5 करोड से अधिक मामले लम्बित है एवं एक मामले के निपटान का औसत समय 2.5 से 3 वर्ष है।

पारम्परिक तरीका

- वाद-प्रतिवाद व्यवस्था
- महंगी
- अधिक समय
- अपीलीय प्रक्रिया से अनवरत विलम्बन

ADR

- यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त पर आपसी सहमति पर आधारित है।

बेहतर विकल्प - तर्क

- दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निर्णय

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

↳ परम्परागत कोर्ट फीस, वकील फीस आदि का खर्च नही

↳ स्थानीय न्याय उपलब्धता

सीमाएँ

↳ सरकार द्वारा सीमित खर्च
वार्षिक लोक अदालतों का आयोजन

↳ राज्यानुसार भिन्नता

↳ 'अंतिम निर्णय' की अवधारणा की विश्वसनीयता में कमी

सरकारी प्रयास

↳ राष्ट्रीय लोक अदालत अधिनियम

↳ ग्राम न्यायालय

↳ ई-अदालत

↳ मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 2019

↳ NALSA 1987

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

आगे की राह

- आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों के 2187 पदो तथा उच्च न्यायपालिका के 287 पदो की रिक्ति पूर्ण करके लम्बित मामलो को 3 वर्ष में निपटान किया जा सकता है
- ADR के लिए ~~संस्थागत~~ अवसंरचना तथा जागरूकता का प्रसार के लिए विधायी सशक्तता प्रदान करना।
- समयबद्ध निपटान के लिए विधायी प्रावधान
- BNNS, BSA, BAC की भाँति अन्य पुराने कानूनों का तार्किकीकरण

समय पर न्याय मिलना आवश्यक है क्योंकि "Justice Delayed is Justice Denied"

drishti | दृष्टि The Vision

14. दिल्ली के शासन और भारत के संघीय ढाँचे पर इसके संभावित प्रभाव पर विचार करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन (GNCTD) (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रावधानों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

(250 शब्द) 15

Critically examine the provisions of the Government of National Capital Territory of Delhi (GNCTD) (Amendment) Act, 2023 considering its potential impact on the governance of Delhi and the federal structure of India.

(250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239AA में विशेष प्रावधान के माध्यम से NCT में विधानसभा तथा UT की निर्वाचित सरकार का प्रावधान किया गया है।

दिल्ली का शासन

- भूमि, पुलिस जैसे राज्य सूची के विषयों पर केन्द्र सरकार का नियंत्रण होगा।
- उपराज्यपाल कार्यकारी प्रमुख
- राष्ट्रपति व UT सरकार के मध्य कड़ी का कार्य उपराज्यपाल

भारत का संघीय ढाँचा

- परम्परागत संघीय ढाँचा (USA) से

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

पृथक ढाँचा है जिसमें केन्द्र-राज्य संबंधों में शक्ति का विभाजन (7वीं अनुसूची) है परन्तु झुकाव केन्द्र की ओर है।

↳ दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है अतः केन्द्र-दिल्ली संबंध भारतीय संघीय ढाँचे से भी पृथकता रखते हैं।

GNCTD (संशोधन) अधिनियम 2023

→ नौकरशाही की पदस्थापना व स्थानान्तरण से संबंधित अंतिम निर्णय उपराज्यपाल द्वारा लिए जाएंगे।

↳ इससे निर्वाचित सरकार तथा केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उपराज्यपाल की शक्तियों के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

↳ इससे पूर्व SC ने NCT बनाम भारत संघ वाद में निर्णय दिया था कि उपराज्यपाल निर्वाचित सरकार की सलाह पर कार्य करेंगे। SC के इस निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए वर्तमान कानून लाया हुआ प्रतीत होता है।

आगे की राह

↳ अधिनियम की संवैधानिकता का प्रश्न SC के समक्ष लम्बित है अतः उसका जल्द निपटान हो

↳ राजनीतिक समस्याओं/टकरावों का समाधान आपसी संवाद से हो

लोकतंत्र में जनता की इच्छा सर्वोपरि होती है जिसका प्रतिनिधित्व निर्वाचित सरकार करती है अतः उसकी वैधता की सुनिश्चितता एवं शक्ति संतुलन अपरिहार्य है।

drishti | दृष्टि The Vision

15. भारतीय लोकसभा और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में अध्यक्ष की भूमिका की तुलना कीजिये। चर्चा कीजिये कि ये भूमिकाएँ अपने-अपने विधायी निकायों की कार्यप्रणाली को कैसे प्रभावित करती हैं। (250 शब्द) 15

Compare and contrast the role of speaker in the Indian Lok Sabha and British House of Commons . Discuss how these roles impact the functioning of their respective legislative bodies. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय संसदीय प्रणाली औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन प्रणाली से प्रभावित है।

अध्यक्ष की भूमिका

समानताएँ

- सदन की सुचारु कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- प्रतिनिधित्व के आधार बैठक व्यवस्था, बोलने का समय, समितियों का गठन आदि करवाना
- संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सदस्यों का निलम्बन या बर्खास्तगी संबंधी अधिकार

भिन्नताएँ

- लोकसभा अध्यक्ष को 52 वें संविधान

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

संशोधन द्वारा दल बदल कानून (10वीं अनुसूची) में सदस्यों की अयोग्यता निर्धारण की शक्ति है।

↳ हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष के पास शैडो कैबिनेट गठन का क्षेत्राधिकार

↳ भारत में लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा नियमों के लिखित स्वरूप से संचालन करते हैं जबकि इंग्लैण्ड में परम्पराओं आधारित संचालन है।

↳ भारत में संविधान की सर्वोच्चता की स्थिति है जबकि इंग्लैण्ड में संसदीय सर्वोच्चता पर आधारित राजशाही शासन व्यवस्था है।

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

विधायी निकायों की कार्य प्रणाली पर प्रभाव

भारत में लोकसभा अध्यक्ष का कार्यक्षेत्र व्यापक परन्तु नियमबद्ध है जबकि इंग्लैण्ड में अधिक शक्ति युक्त परन्तु परम्पराओं से आबद्ध है।

संसदीय प्रणाली का मूल तत्व के रूप में कार्यपालिका पर नियंत्रण दोनों व्यवस्थाओं का अंतिम उद्देश्य है।

ब्रिटेन में सर्वाधिक प्राचीन संसदीय प्रणाली है तो भारत की विशाल संसदीय व्यवस्था है।

16. राजकोषीय संघवाद सुनिश्चित करने एवं केंद्र और राज्य सरकारों की राजकोषीय शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखने में वित्त आयोग की महत्त्वपूर्ण भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द) 15

Critically evaluate Finance Commission's crucial role in ensuring fiscal federalism and maintaining a balance between the fiscal powers of the central and state governments. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है।

कार्य

↳ वित्त आयोग के कार्यों का निर्धारण Terms of References के अनुसार किया जाता है।

↳ प्रमुख कार्य केन्द्र व राज्य सरकारों में मध्य संसाधनो का क्षैतिज व लम्बवत विभाजन करना है। (15 वें वित्त आयोग द्वारा राज्यो को करो का 42% हिस्सा प्रदान किया गया)

राजकोषीय संघवाद

↳ केन्द्र व राज्य सरकारों के मध्य वित्त का विभाजन संघवाद अर्थात केन्द्र व राज्य

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

को समान शक्तियों के सिद्धान्त के आधार पर किया जाता।

वित्त आयोग की सीमाएँ

- अनुशंसात्मक संस्था
- 5 वर्षों में एक बार गठन जबकि विवाद के मुद्दे निरन्तर चलते रहते हैं
- Terms of References पर आधारित अनुशंसाएँ
- अनुच्छेद 246 के अंतर्गत राज्यों द्वारा बाह्य ग्रहण की सीमा का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा (5% of GSDP)
- कर संग्रह में राज्यों के योगदान में भारी अंतर (दिल्ली महाराष्ट्र का इनकम टैक्स में योगदान लगभग 40%)
- संसाधन स्रोतों की विषमता ~~तथा~~ (दक्षिण > उत्तर) तथा विकास की क्षेत्रीय विषमता (दक्षिण > उत्तर) से असंगत स्थिति

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

आगे की राह

↳ N.K. सिंह समिति की अनुशंसा के अनुसार राजकोषीय समेकन तथा ऋण का GDP से अनुपात (60% → 40% केंद्र तथा 20% राज्यों) की अनुपालना की जाए

↳ राज्यों को अपने स्तर पर नये संसाधनों (आय स्रोतों) का विकास करना
जैसे DISCOM की स्थिति सुधारना

↳ केन्द्र द्वारा राज्यों को पूँजीगत व्यय के लिए संवैधानिक अनुदान प्रदान करना (बजट 2024-25 में बिहार व AP)

भारत जैसे विकासशील देश में तीव्र विकास के लिए सहकारी एवं 'प्रतिस्पर्द्धात्मक संघवाद' की आवश्यकता है।

drishti | दृष्टि The Vision

17. क्या भारत ने अपनी वैश्विक स्थिति और प्रभाव को बढ़ाने के लिये अपनी सॉफ्ट पावर का लाभ उठाया है? विश्लेषण कीजिये।
(250 शब्द) 15

Has India leveraged its soft power to enhance its global stature and influence? Analyze.
(250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

सॉफ्ट पावर से तात्पर्य है किसी देश की सांस्कृतिक विशिष्टता तथा नागरिकों के सीधे जुडाव का अंतर्राष्ट्रीय संबंधो में प्रयोग करना।

सॉफ्ट पावर का प्रभाव

→ अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में भारतीय मूल के लोगों के प्रभाव के कारण अमेरिका का भारत की ओर झुकाव (HOWDY मोदी, नमस्ते ट्रम्प जैसे कार्यक्रम)

→ दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय उपग्रह द्वारा SAARC देशों में संचार सुविधाएँ

→ NAVIC का SAARC देशों में प्रयोग

→ वैक्सीन डिप्लोमेसी द्वारा अफ्रीकी

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

देशों में कोविड वैक्सीन का निर्यात

↳ मानवीय आधार पर अफ्रीकी देशों में जेनेरिक दवाएँ निर्यात करना

↳ तृतीय विश्व (WTO-G33), G20 प्लस, NAM जैसे मंचों पर विकासशील देशों का पक्ष मुखरता से रखना

↳ UNFCCC के COP-28 में जलवायु न्याय की अवधारणा

↳ विश्व प्रवसन रिपोर्ट के अनुसार

सर्वाधिक प्रवासी तथा रेमिटेंस

↳ गिरमिटिया देशों में भारतीय मूल के लोगों द्वारा महत्वपूर्ण राजनीतिक पद धारण करना (मॉरिशस के राष्ट्रपति)

↳ अफगानिस्तान में क्षमता निर्माण

↳ संसद, सलमा डैम, राजमार्ग

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

↳ श्रीलंका को वित्तीय सहायता।

लाभ

↳ G-20 अध्यक्षता में भारत का मजबूत पक्ष विश्व के सम्मुख रखना।

↳ UN स्थायी सदस्यता पर दावा प्रबल।

↳ राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण।

↳ पश्चिम एवं पूर्व के साथ एक साथ संबंध संतुलन (RIC & QUAD)

भारत की विदेश नीति परम्परागत आदर्शवाद से सक्रिय यथार्थवाद की ओर बढ़ रही है।

drishti | दृष्टि The Vision

18. अपनी स्थापना के बाद से पिछले दो दशकों से अधिक समय में, बिम्सटेक (BIMSTEC) ने अपनी विशाल क्षमता का उपयोग करते हुए सामूहिक उन्नति की दृष्टि वाले समूह के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने में एक लंबा सफर तय किया है। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द) 15

In the past more than two decades since its establishment, BIMSTEC has come a long way in distinguishing itself as a group with a vision for collective advancement utilizing its vast potential. Comment. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

drishti | दृष्टि The Vision

19. उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते वैश्विक ऋण संकट के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पड़ने वाले प्रमुख परिणामों का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15

Examine the major outcomes of soaring global debt crisis in emerging and developing economies on international relations. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

20. यूरोप का हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर बढ़ता ध्यान तथा भारत के साथ गहराता आर्थिक और तकनीकी सहयोग परस्पर लाभ प्रदान करता है। चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Europe's increased focus on the Indo-Pacific and the deepening economic and technological collaboration with India offer mutual benefits. Discuss. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

Space for Rough Work

(रफ कार्य के लिये स्थान)

drishti | दृष्टि The Vision

Space for Rough Work

(रफ कार्य के लिये स्थान)

drishti | दृष्टि The Vision

Space for Rough Work

(रफ कार्य के लिये स्थान)

Space for Rough Work

(रफ कार्य के लिये स्थान)